

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- मेघना चौधरी, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:-116/2021/225 (2021/116)

1. श्रीमती कमलेश पत्नि अमरसिंह, जाति माली, निवासी 1018, मायरा बेरा, संस्कार कॉलोनी, गुलाब बाड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांत

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र कालीचरण, जाति कोली, नि० धोलाभाटा, आनन्दपुरी, अजमेर तहसील व जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 25.3.2021 अंतर्गत प्रकरण संख्या 16/2021.

उपस्थित:-

1. श्री अभिषेक शर्मा, वकील अपीलांत ।
2. श्री ए०के० माथुर, वकील रेस्पोंड संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 2.



निर्णय

दिनांक:- 24.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 25.3.2021 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांत ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज०काश्त० अधि० के तहत पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी जिसके साबिक खसरा नंबर 1852 व हाल खसरा नंबर 1590 है का भाग है जो कि प्रार्थिया के पति अमरसिंह के द्वारा जरिये इकरारनामा संपूर्ण बेचान, मुख्तारनामा आम, वसीयत के जरिये गुलाब पुत्र मदनलाल जो कि आराजी का सहखातेदार है, से क्रय किया था तथा क्रय दिनांक 14.12.1993 को कब्जा प्राप्त किया था । उक्त इकरारनामा संपूर्ण बेचान बाबत एक मुश्त 24000/-रु० की राशि गुलाबचंद को अदा की गई थी तथा उक्त तीनों दस्तावेज नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक किये गये थे । गुलाबचंद चौहान की मृत्यु दिनांक 8.3.2014 को हो गई थी । इस प्रकार वसीयतनामा दिनांक 14.12.1993 के आधार पर उक्त सम्पति पर हाल प्रार्थिया के पति अमरसिंह के पति को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है । उक्त वसीयत के आधार पर हाल प्रार्थिया के पति ने एक उपहार विलेख दिनांक 26.12.2019 को प्रार्थिया के पक्ष में निष्पादित कर दिया था । हाल में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जबरन दिनांक 29.7.2020 को दोपहर 12 बजे उक्त सम्पति पर कब्जा करने की कोशिश की गई जिसकी शिकायत हाल अपीलांत द्वारा पुलिस थाना अलवर गेट अजमेर में दिनांक 3.7.2020 को की गई उसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पुनः उक्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तथा उक्त प्लाट पर

WSM
राजस्थान राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

मंदिर निर्माण हेतु पर्चे छपवाये तथा मौके पर कुछ निर्माण सामग्री भी डलवाई गई । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी०न्याया० ने अपने आदेश दिनांक 25.3.2021 के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 खारिज कर दिया । अधी०न्याया० के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी०न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी०न्याया० ने तीनों बिन्दुओं प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण्य क्षति पर कोई विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय तीनों बिन्दुओं पर विवेचन कर समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं कानूनी प्रावधानों का विवेचन करते हुए प्रार्थना पत्र को निर्णित करना चाहिये था । अधी०न्याया० ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का आधार यह माना कि अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में बहसियत खातेदार दर्ज नहीं है परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार नामांतरण नहीं होने से किसी के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं । गुलाबचंद के द्वारा दिनांक 14.12.1993 को सम्पत्ति के बाबत जो वसीयत हाल अपीलांट के पति के पक्ष में की गई उससे अपीलांट के पति को उक्त सम्पत्ति में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे इसके पश्चात् दिनांक 26.12.2019 को अपीलांट के पति ने पंजीकृत उपहार विलेख अपीलांट के नाम से निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा दिया जिससे वह समस्त खातेदारी अधिकार अपीलांट को प्राप्त हो गये तथा रेस्पो० संख्या 1 के द्वारा जो पंजीबद्ध विलेख प्रस्तुत किया गया है वह पंजीकृत विलेख पश्चात्वर्ती विलेख है जिसके आधार पर रेस्पो० संख्या 1 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अधी०न्याया० ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जिस दस्तावेज के आधार पर हाल रेस्पो० संख्या 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है उन दस्तावेजों के बाबत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0078/21 दिनांक 14.3.2021 को अपराध अंतर्गत धारा 420, 406 भा०द०सं० के तहत दर्ज की गई जिसका अनुसंधान विचाराधीन है । इसलिये उक्त पश्चात्वर्ती दस्तावेज प्रथम दृष्टया ही संदेहास्पद है । यह भी कथन किया कि राजस्थान धार्मिक भवन व स्थल अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत कोई भी व्यक्ति बिना कलक्टर की आज्ञा के किसी भी स्थल पर मंदिर का निर्माण नहीं करवा सकता है जबकि हाल में रेस्पो० संख्या 1 ने अपने जवाब में साफ तौर पर यह अंकित किया है कि वह उक्त सम्पत्ति पर मंदिर निर्माण कार्य करना चाहता है । ऐसी स्थिति में भी रेस्पो० को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक था । अधी०न्याया० ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को नजरअदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी०न्याया० का आदेश निरस्त किया जावे तथा वाद के निर्णय तक रेस्पो० संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।
5. विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी०न्याया० का आदेश विधिसम्मत है । भूखण्ड संख्या 11 जो किरानीपुरा गांव में पुराना खसरा संख्या 1852 तथा नया 1590 का एक भाग है जिसका क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज है जो कपिल वस्तु कॉलोनी धोला भाटा, अजमेर में स्थित है । इस भूखण्ड पर रेस्पो० संख्या 1 का कब्जा है तथा निर्माण किया हुआ है । इस भूखण्ड पर कभी भी अपीलांट का कब्जा नहीं रहा



(Signature)
 राजस्थान न्यायालय
 अजमेर

है । खसरा नंबर 1852 जिसका नया नंबर 1590 बना है उसमें हीरालाल पुत्र रामदेव का 1/20 हिस्सा था और हीरालाल पुत्र रामदेव ने विधिवत् गवाहों के समक्ष एक मुख्तयारनामा दिनांक 28.12.1992 को घनश्यामसिंह पुत्र रामचंद्र चौधरी के पक्ष में निष्पादित किया था तथा जिसे बाद में विधिवत् नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराया था । उक्त मुख्तयारनामा कभी भी निरस्त नहीं किया गया है ना ही निरस्त हुआ है । इस मुख्तयारनामे के जरिये उक्त घनश्यामसिंह द्वारा विधिवत् पंजीकृत विक्रय पत्र के भूखण्ड का कब्जा रेस्पो0 संख्या 1 को संभला दिया था । गुलाबचंद्र चौहान के साथ कोई इकरारनामा दिनांक 14.12.1993 को अमरसिंह पुत्र सूरजमल ने नहीं किया था । तथाकथित इकरारनामा ना तो विधिवत् रूप से निष्पादित है और ना ही यह उचित स्टाम्प पर होकर पंजीकृत है । अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर अपीलांट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । गुलाबचंद्र का खसरा संख्या 1852 नया नंबर 1590 में 1/28 हिस्सा था । खसरा नंबर 1590 का रकबा 1-7-00 रहा है । जमाबंदी के अनुसार 1/8 हिस्सा अर्थात् 500 वर्गगज से ज्यादा नहीं हो सकता है । रेस्पो0 पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर कब्जा प्राप्त कर भूखण्ड पर निर्माण कर रहा है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र अपंजीकृत इकरारनामा संपूर्ण बैचान, मुख्तयारनामा व वसीयतनामा एवं इकरारनामा संपूर्ण बैचान दिनांक 14.12.1993 के आधार पर पेश कर वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/अपीलांट विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने तथा कब्जा होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं । अपीलांट प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रही है । प्रार्थी को तथाकथित अपंजीकृत इकरारनामे से क्या हक व अधिकार प्राप्त होते हैं इन तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा । रेस्पो0 ने विवादित आराजी पर कब्जा होने का कथन किया है यदि रेस्पो0 को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपूर्ण क्षति अपीलांट के बजाय रेस्पो0 को होने की संभावना है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्ण क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रही है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.3.2021 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)

राजस्व अपीलांट प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)

राजस्व अपीलांट प्राधिकारी,
अजमेर

